देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 14 अंकः 259 पृष्ठ : 8 मूल्यः एक रूपए

विचार-प्रवाह...यह खूनी समाज

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 23 नवंबर 2019

मौसम अधिकतम 23.0° न्यूनतम 13.0° 40359.41

2 नहीं चुन सकता दलाई लामा का वारिस 7 लिटन के हेलमेट पर लगी शमी की गेंद

मौकापरस्ती का गठबंधन टिकेगा नहींः नितिन गडकरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

काम के दम पर जीतेंगे झारखंड

■कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में वैचारिक नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के संभावित गठबंधन को नितिन गडकरी ने मौकापरस्ती का गठबंधन बताया है। महाराष्ट्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी गडकरी ने कहा कि वैचारिक तालमेल ना होने के कारण यह गठबंधन टिकेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना होना देश, विचारधारा, हिंदुत्व और महाराष्ट्र के लिए नुकसानदायक है।

कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के बीच होने जा रहे गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इनके बीच वैचारिक तालमेल नहीं है। शिवसेना जिस विचारधारा पर चलती है, कांग्रेस उसका पूरी तरह से विरोध करती है। कांग्रेस जिस विचारधारा पर चलती है, उसका शिवसेना विरोध करती है। एनसीपी भी शिवसेना के विचारों से तालमेल नहीं रखती है।

उन्होंने आगे कहा, विचारों और सिद्धांतों के आधार पर यह गठबंधन नहीं हुआ है। यह मौकापरस्ती का गठबंधन है। यह टिकेगा नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगा। इसमें महाराष्ट्र का काफी नुकसान होगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए अस्थिर सरकार अच्छी बात नहीं है।

शिवसेना के साथ गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी सरकार क्यों नहीं बना पाई, इसपर गडकरी ने कहा, इतिहास तो सबको पता है। प्रश्न यह है कि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था, वह हिंदुत्व के विचारों पर आधारित था। इसलिए यह देश में सबसे लंबा अलायंस साबित हुआ है।

झारखंड में बीजेपी की जीत का विश्वास जताते हुए नितिन गडकरी ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में स्थिर सरकार के अंतर्गत जो काम किए गए हैं, मुझे भरोसा है कि राज्य के लोग एक बार फिर से रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी को फिर से चुनेंगे।

बीजेपी के झूठ से छोड़ा 25 साल पुराना साथ

शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुंबई। महाराष्ट्र में अपनी धुर विरोधी एनसीपी-कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाने जा रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने शिवसेना विधायकों के साथ बैठक में कहा कि एनसीपी-कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की नौबत बीजेपी की वजह से आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे को दिया वचन तोड़ा और दोबारा चुनाव न कराने पड़ें इसलिए हमने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया।

सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में शिवसैनिकों के साथ बैठक में कहा, कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने की नौबत बीजेपी की वजह से आई है। बीजेपी ने बाला साहेब को वचन दिया था कि शिवसैनिक सीएम बनेगा। बीजेपी ने अपना वादा तोड़ा है। दोबारा चुनाव न हो, इसलिए हमें यह फैसला लेना पड़ा। उद्धव ने अपने विधायकों से साफ कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

कुछ रिश्तों से बाहर आना ही अच्छाः राउत

संजय राउत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, महाराष्ट्र में 5 साल तक होगा शिवसेना का सीएम होगा। अगले दो दिनों में तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। हालांकि शिवसैनिकों और महाराष्ट्र के जनता की प्रबल इच्छा है कि उद्धव ठाकरे सीएम बनें। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना के नेता के सीएम बनने की घड़ी आ गई है। शिवसेना के सीएम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने भी अपनी सहमती दे दी है। शिवसेना नेता ने कहा, शिवसेना को भगवान इंद्र के सिंहासन का प्रस्ताव मिले तब भी वह बीजेपी के साथ नहीं आएगी।

संक्षिप्त समाचार

भारत-बांग्लादेश का पहला डे-नाइट टेस्ट मैच देखने कोलकाता पहुंची शेख हसीना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले डे-नाइट टेस्ट मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ईडन गार्डन्स पहुंचीं। दोनों ने बाद में घंटा बजाकर मैच की आधिकारिक शुरुआत भी की। डे-नाइट मैच होने की वजह से ये मुकाबला पिंक बॉल से खेला जा रहा है। इस वजह से इसे पिंक बॉल टेस्ट मैच भी नाम दिया गया है। खास बात ये है कि दोनों टीमें शुक्रवार को पहली बार पिंक बॉल टेस्ट (डे-नाइट टेस्ट) मैच खेलने के लिए मैदान में उतरीं। पहली बार भारत-बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है।

कोर्ट का केंद्र और यूआईडीएआई को नोटिस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) सुप्रीम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाल ही में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जिसमें निजी संस्थाओं को आधार डेटा तक पहुंच की सुविधा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जिसमें निजी संस्थाओं को ग्राहकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

चीन से जल्दी घटाएंगे प्रदूषण

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम बीजिंग से भी कम समय में दिल्ली में वायु प्रदूषण कम कर देंगे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा कि बीजिंग को वायु प्रदूषण से निपटने में 15 साल लगे हम इससे भी कम समय में दिल्ली में वायु प्रदूषण कम कर देंगे। पर्यावरण मंत्री ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब हो गई है।

लोकसभा में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने कहा, 'वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। इससे हम सभी को मिल कर निपटना है और इसके लिए सतत प्रयास जरूरी है।' मंत्री ने कहा, 'बीजिंग को वायु प्रदूषण से निपटने में 15 साल लगे हैं, हम इससे कम समय में इसे (वायु प्रदूषण को) मात देंगे।'

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति

जावड़ेकर दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में वायु प्रदूषण के बारे में सदस्यों की चिंताओं पर जवाब दे रहे थे। उधर, शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक दो दिनों में हवा की गति तेज होगी और स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। हवा की गुणवत्ता 25 नवंबर को फिर से खराब हो सकती है। दोपहर दो बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रहा। रोहिणी इलाका सबसे प्रदूषित रहा। यहां एक्यूआई 416 रहा।

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के लिए मंगलवार को लोकसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए शहर के बीजेपी सांसदों ने कहा था कि वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोकसभा में नियम 193 के तहत प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के दौरान बीजेपी सदस्यों ने कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना नहीं, बल्कि यहां वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण गतिविधियां हैं।

मास्क बांटना बहुत बड़ा घोटाला

बीजेपी सदस्य परवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वह ऐसे मास्क बांट रहे हैं जिसके बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दावा है कि ये प्रदूषण से नहीं बचा सकते। उन्होंने आरोप लगाया, 'दिल्ली सरकार ने 50 लाख मास्क बांटे। लेकिन कोई निविदा जारी नहीं की गई। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है।'बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि प्रदूषण के मामले पर आरोप-प्रत्यारोप और सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

रेलवे भारत और भारतवासियों की संपत्ति

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

रेलवे के निजीकरण पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया

नई दिल्ली। रेलवे के निजीकरण की चर्चाओं के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे भारत और भारतीयों की संपत्ति है और आगे भी रहेगी। गोयल ने रेलवे के निजीकरण की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निजी कंपनियों से कॉमर्शल और ऑन-बोर्ड सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर रही है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे को चलाने के लिए अगले 12 वर्षों में अनुमानित तौर पर 50 लाख करोड़ रुपये की पूंजी सरकार अकेले नहीं जुटा सकती, इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। ऊपरी सदन में गोयल ने कहा, हमारा मकसद यात्रियों को बेहतर सेवाएं और फायदा देना है, न कि रेलवे का निजीकरण करना।